

43.65 करोड़ रुपये हाई वे नं० 6 और 7 के लिए चाहियें। इस साल 5.90 करोड़ प्रोवाइड किए हैं और जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि जो काम इस करेंट अलोकेशन में आता है, उसको पूरा करा सके।

श्री देवराव पाटील : श्रीमन्, इसमें जो तीन बड़े राजमार्ग नं० 6 पर रायपुर-नागपुर खंड में और वर्धा जिले में वर्धा-नागपुर-आंध्र प्रदेश की सीमा पर जो धन-राशि रखी है 1976-77 के लिए, उसमें से कितनी रकम खर्च होगई है?

डा० जी० एस० ढिल्लों : आपने वर्धा से लेकर कहाँ तक पूछा था?

श्री देवराव पाटील : वर्धा से नागपुर तक।

डा० जी० एस० ढिल्लों : अगर आप चाहेंगे तो मैं ये आंकड़े इकट्ठे करके दे दूंगा। मेरे पास इस समय स्टेट-वाइज लिस्ट है। विस्तार से अगर आप चाहते हैं तो नोटिस भी आप न दें, वैसे ही आपको दे दूंगा।

Children below 14 years employed In small factories in Delhi

*362. SHRI SYED AHMAD HASHMI : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government are aware that children under 14 years of age are employed in small factories in Delhi in hazardous jobs; and

(b) whether there is a proposal under Government's consideration to conduct a survey with a view to detecting cases of exploitation of such children and to put an end to this malpractice?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI BAL-GOVIND VERMA) : (a) and (b) According to the information furnished by Delhi Administration, no such case has come to their notice in respect of registered factories under the Factories Act, 1948. However, Delhi Administration, on their own, have started a survey to detect cases of employment of children below the age of 14 years in hazardous operations in registered factories.

श्री सैद अहमद हाशमी : ایہی ہمارے منسٹر صاحب نے بتایا کہ کوئی اطلاع ایسی آپ کے پاس نہیں ہے لیکن صورت حال یہ ہے کہ ایسی بہت سی فیکٹریاں ہیں جو مضر صحت ہیں جیسے شیشی پھونکنے کا کام ہے تیزاب کو اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اور زیادہ تر بچے اس کا کام کرتے ہیں اسی طرح سے اور بھی بہت سی صنعتیں ہیں۔ اس لئے کہ ویجیز انہیں کم دینے پڑتے ہیں اس لئے ان میں بچوں کا استعمال کیا جاتا ہے اس لئے انفارمیشن کا نہ ہونا ایسا نہیں ہے کہ ایسی چیز ہو نہیں رہی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا کام جو ہونا ہے وہ عموماً معاشی اور اکانامیکی طور پر اقتصادی طور پر جو گہرانے یا جو کنبے بہت ہی پشماندہ ہیں اور کوئی شکل نہیں ہوتی ہے اپنا پیٹ پالنے کے لئے۔ تو بچے خود یا والدین اپنے بچوں کو ان کاموں پر لگا دیتے ہیں کیا کوئی ایسی اسکیم ہے کہ اس قسم کے بچے ملیں تو ایک طرف ان کی فری ایجوکیشن کا انتظام کیا جائے دوسری طرف یہ کہ ایسے کنبوں کو جن کے بچے ہی کچھ کر سکتے ہیں ان کے لئے ان کنبوں کے لئے ایسا انتظام کیا جائے جس سے کہ وہ معاشی طور پر خود کفیل ہو سکیں۔

†[श्री सैयद अहमद हाशमी : अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने बतलाया कि कोई

†[] Hindi translation.

इतिलाह ऐसी आपके पास नहीं है लेकिन सुरतेहाल यह है कि ऐसी बहुत सी फैक्टरियां हैं जो मुजिर सेहत हैं—जैसे श्रीशी फूकने का काम है, तेजाब को इसके अन्दर इस्तेमाल किया जाता है और ज्यादातर बच्चे इसका काम करते हैं। इस तरह से और भी बहुत-सी सनतें हैं—इसलिए कि वेजेज इन्हे कम देने पड़ते हैं, इसलिए इनमें बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन्फार्मेशन का न होना, ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज हो नहीं रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा काम जो होता है, वह अमूमन मुआशी और एकानामीकली तौर पर इक्तासादी तौर पर जो धराने या जो कुनवे बहुत ही पसमान्दा हैं और कोई शकल नहीं होती है, अपना पेट पालने के लिए—तो बच्चे खुद या बालदेन अपने बच्चों को इन कामों पर लगा देते हैं। क्या कोई ऐसी स्कीम है कि इस किस्म के बच्चे मिलें तो एक तरफ उनकी प्री एजुकेशन का इन्तजाम किया जाये, दूसरी तरफ यह कि ऐसे कुनवों को, जिनके बच्चे ही कुछ कर सकते हैं उनके लिए, उन कुनवों के लिए ऐसा इन्तजाम किया जाये, जिससे कि वे मुआशी तौर पर खुद फर्कल हो सकें।]

श्री बाल गोविन्द वर्मा : श्रीमन्, बच्चों की नौकरी हमारे दो कानूनों के अन्तर्गत आती है—फैक्टरीज ऐक्ट, 1948 और चिल्ड्रन एम्प्लायमेंट ऐक्ट, 1938। फैक्टरीज ऐक्ट के अन्तर्गत धारा 67 के अन्तर्गत यह प्रतिबन्ध है कि 14 साल से कम के बच्चे नौकरी में नहीं लगाये जा सकते हैं, लेकिन अंडर दी शाप्स एण्ड एस्टाब्लिशमेंट ऐक्ट, चिल्ड्रन एम्प्लायमेंट ऐक्ट में हम एलाउ करते हैं—केवल दो को छोड़ कर—एक तो ट्रेनिंग प्रोसेस और एक सोप मेकिंग प्रोसेस है—इनके अन्दर हम 15 साल से नीचे के बच्चों को नहीं लेते, जैसे—ट्रांसपोर्ट आफ पैसिजर्स, गुड्स एण्ड मेल्स बाई रेलवेज, इन एनी आकु-पेशन अंडर दी पोर्ट अथारिटी विदिन दी

लिमिट्स आफ एनी पोर्ट। एम्प्लायमेंट आफ चिल्ड्रन आफ अपटू 14 इयर्स इन बीड़ी मेकिंग, कारपेट बीविंग, सीमेंट मेनुफैक्चरिंग क्लाय मेनुफैक्चर, मेनुफैक्चर आफ फायरवर्क्स, मना हैं। दिल्ली में जहाँ तक साबुन बनाने का काम होता है, चमड़ा रंगने का काम होता है, या पकाने का काम होता है, उनमें बच्चे कतई इस्तेमाल नहीं किए जाते, लेकिन और जगहों पर 12 से 14 साल तक के बच्चे इस्तेमाल होते हैं। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इस पर बड़ी अच्छी तरह से विचार कर रही है कि 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को कहीं भी इस्तेमाल न किया जाए।

जहाँ तक बच्चों के एम्प्लायमेंट की बात है, हम सभी लोग जानते हैं कि 14 वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए एम्प्लायमेंट हानिकारक है, लेकिन अपने देश की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए बड़ा मुश्किल है। अभी हमारे यहाँ की आर्थिक हालत सुधरी नहीं है। जैसे ही हालत में सुधार हो जाएगा हम बच्चों को इन कामों से दूर रखेंगे। जहाँ तक पढ़ाई की बात है, माननीय सदस्य ने बड़ा अच्छा सजेशन दिया है, उस पर हम विचार करेंगे।

شری سید احمد ہاشمی : سر—

قانون تو بنتے رہتے ہیں اور بنتے رہیں گے اس ایمر جنسی کا نفاذ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جن قانونوں پر عمل نہیں ہو رہا ہے ان پر عمل کیا جائے۔ ہمارے آنریبل منسٹر صاحب نے بھی اس بات پر توجہ دلائی ہے کہ باوجود پابندیوں کے یہ صورت حال اپنی جگہ پر قائم ہے اور بہت مجبوریوں کے ماتحت اور اقتصادی مجبوریوں کے ماتحت وہ بھی جن کی عمر تعلیم کی ہے کام کرنے کے لئے

मजबूर हैं कियों के बना उन
का गहरा नहीं चल सकता—मिरा मवाल
ये तह कि उन मजबूरों को दूर करने
के सिलसले में किया कोनी अस्किम लीवर
मन्शरी के पास है या नहीं -

[श्री सैयद अहम हाशमी : सर, कानून तो बनते रहते हैं और बनते रहेंगे—इस एमर-जेंसी का नफाफा करने का मतलब यह था कि जिन कानूनों पर अमल नहीं हो रहा है, उन पर अमल किया जाये। हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब ने भी इस बात पर तबज्जो दिलाई है कि वावजूद पाबंदियों के यह सुरतेहाल अपनी जगह पर कायम है और बहुत मजबूरियों के मातहत और इकत-सादी मजबूरियों के मातहत वे बच्चे जिनकी उम्र तालीम की है, काम करने के लिए मजबूर हैं; क्योंकि इसके बिना उनका घर नहीं चल सकता। मेरा सवाल यह था कि इन मजबूरियों को दूर करने के सिलसिले में क्या कोई स्कीम लेबर मिनिस्ट्री के पास है या नहीं ?]

श्री बाल गोविन्द वर्मा : श्रीमन्, आप जानते हैं और सभी माननीय सदस्य भी जानते हैं कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि जिन बातों की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है उनको दूर कर सकें, कोशिश जरूर जारी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी काम हम कर रहे हैं वे लेबर की भलाई के लिए कर रहे हैं। हमेशा यह प्रयत्न रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा उनको राहत देकर उनकी परेशानी को दूर करें।

SHRI BHUPESH GUPTA : With regard to children under fourteen. I should like to know what steps the Government have taken in order to save such children from being exploited in this manner not only by small factories, but by shops, commercial undertakings and even private individuals including Ministers. I should like to know whether the Government has any scheme for conducting a national survey of

children below 14 years employed and exploited in this manner by various elements and for their care and education under the aegis of the State in pursuance of the Directive Principles of State Policy. I should like to know whether any steps will be taken so that in this country children below 14 years, whether in the rural areas or in the urban areas, shall not be subjected to exploitation either by private individuals or concerns or by any other organisations of this type including factories and so on.

MR. CHAIRMAN : This question pertains to Delhi only.

SHRI BHUPESH GUPTA : What ?

MR. CHAIRMAN : I said that this question pertains to Delhi only.

SHRI BHUPESH GUPTA : You see, you are in Delhi. But do you belong to Delhi ? It is like this only What I say is that Delhi should set an example.

MR. CHAIRMAN : All right.

SHRI BALGOVIND VERMA : Sir, I do not deny that exploitation of children should be ended. But, so far as we are concerned, we have not received any such complaints. Whenever any such complaints are received, although we have not received any such complaints so far, we will certainly look into the matter and action will be taken to punish those persons who try to exploit children. We will certainly look into such complaints if they are received in future and I fully appreciate the feelings of the honourable Member.

MR. CHAIRMAN : But Mr. Bhupesh Gupta wanted a national survey to be conducted. You reply to that.

SHRI BHUPESH GUPTA : You are right, Sir. He says that they have not received any complaints /at all. But, you know, Sir, children below 14 years of age are not going to lodge complaints with the police. You will have to find out yourself through your own mechanism. You are saying that you will take action if it is so. It is so and everybody knows that. Why not ask the Delhi authorities to find out as to how many children below the age of 14 are exploited in this manner in the various establishments in Delhi and outside and to take steps for their care and their welfare ?

SHRI BALGOVIND VERMA : Sir, so far as the survey is concerned, it is well-nigh impossible to undertake such a survey under these conditions. As time passes, we will not hesitate to take action to undertake such a survey. Delhi has taken upon itself the responsibility of conducting this, sort of a survey and we have got the Directorate of Inspection and there are

various other people and they will continue to look into this matter whenever they come across such things and they will try to punish the people concerned. It is not as if nothing is done and people escape.

श्री हर्ष देव मालवीय : मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को मालूम है कि डोमेस्टिक सर्वेन्ट्स, घरेलू नौकरों के तौर पर, 10 से 14 साल तक के लड़कों को सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक घरों में काम करना पड़ता है ? घरेलू नौकरों की स्थिति यह होती है कि अगर मालिक अच्छा मिल गया तो वह अच्छा व्यवहार करता है वरना इन लोगों के साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता है। उनके काम का कोई समय निश्चित नहीं होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस समस्या की तरफ सरकार का ध्यान गया है ? साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक सर्वेन्ट्स के रूप में 14 वर्ष से कम उम्र के लड़कों का जो बुरे तरीके से शोषण होता है उसको रोकने के लिए सरकार किस प्रकार से व्यवस्था कर रही है ? क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है ?

SHRI B. N. BANERJEE : Sir, the question relates to the employment of children below 14 years in small factories in Delhi. But the honourable Member is referring to the children employed as domestic servants in houses. House is not a factory. If it is a factory, only then his question becomes relevant.

SHRI HARSH DEO MALAVIYA : Sir, he was till the other day secretary, now after coming here, he has started giving his rulings. But it is your duty to decide, Sir.

SHRI BHUPESH GUPTA : Sir, houses are factories and you know it and everybody knows it.

श्री बाल गोविन्द वर्मा : जैसा मैंने पहले कहा था, हम सारे देश में फैक्ट्रियों के बारे में ही अभी तक पता नहीं कर पाये हैं। जहाँ तक घरेलू नौकरों का सवाल है, यह एक मसला जरूर है, लेकिन अगर ये लोग अपनी कोई यूनियन वगैरह बना लें तो हम उनकी मदद कर सकते हैं।

SHRI KHURSHED ALAM KHAN : Sir, I think I represent Delhi and so, I can ask questions with more confidence about Delhi. The honourable Minister has said that if he receives any complaint, he would take necessary action. I am sorry to say that the initiative should come from the Minister and not from the affected children. While the Minister expects these children to lodge complaints, we expect that the Minister or the Ministry will take the initiative and find out the irregularities or the breaches of the rules and regulations that are committed. In this connection, I would like to say that children are employed in small workshops and commercial establishments or they work as self-employed persons in their own houses. So, I would like to know whether any survey of such factories or establishments where such children are working, particularly in the walled city which is the place where normally such complaints are reported has been made.

SHRI BALGOVIND VERMA : Sir, this question relates to the employment of children in hazardous operations and only two operations are considered to be hazardous in Delhi which are, as I said earlier, tanning and soap-making operations. No information has been received from the Delhi Administration that children are employed in these two operations. So far as the other part of the question is concerned, I have already said that the Delhi Administration has started a survey to detect cases of employment of children in hazardous operations in registered factories from the third week of July, 1976. In the first instance, survey of industrial areas has been undertaken, and after it is completed, a survey of other localities will be carried out to find out cases of violations of the provisions of the Factories Act. This is being done, and the Delhi Administration is alive to this situation.

*363. [The questioner (Shri M. S. Abdul Khader) was absent. For answer vide cols. 30-31 infra]

Indigenous production of High Carbon and Alloy Steel

364. SHRI SYED NIZAM-UD-DIN

SHRIMATI SUSHILA SHANKAR
ADIVAREKAR :

SHRI GIAN CHAND TOTU :

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state the steps being taken for complete import substitution of high carbon and alloy steel ?

tThe question was actually asked on the floor of the House by Shri Syed Nizam-ud-Din.